सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

जल है तो कल है

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-4 • 14 JULY TO 20 JULY 2023 • VOLUME 51 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

किसी का भला करके देखो,
हमेशा लाभ में रहोगे,
किसी पर दया करके देखो,
हमेशा याद में रहोगे !

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay Money after the visa

•IELTS •STUDY ABROAD

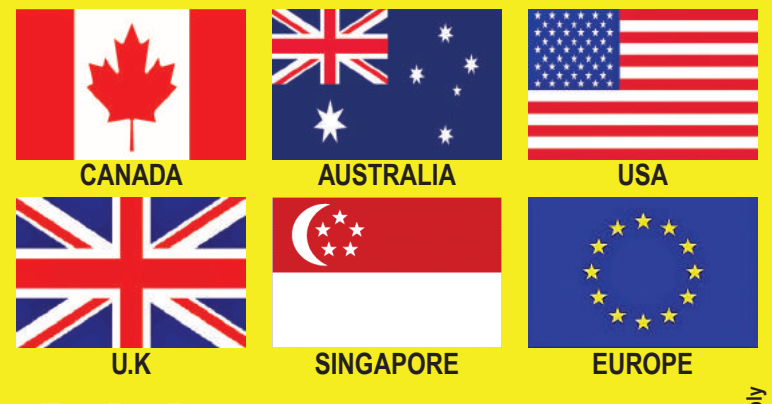

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

सीएम मान ने बाढ़ के पानी में उतर कर लिया राहत कार्यों का जायज़ा

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों के लिए अधिकारियों को मौके पर दिए आदेश

• **जालंधर ब्रीज.** संगरूर

किसी मुख्यमंत्री की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने की पुरानी रिवायत को ख़त्म करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बाढ़ के पानियों में स्वयं उतर कर राहत कामों का जायज़ा लिया। ुख्यमंत्री ने सफ़ेद-कुर्ता पायजामा पहना हुआ था परन्तु राहत कामों की निगरानी करने के लिए वह बिना कोई झिझक महसूस किये राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों और ज़िला प्रशासन के साथ बाढ़ के पानी में उतर गए। भगवंत मान बाढ़ से प्रभावित पानी के साथ भरे खेतों में भी गए जहाँ जेसीबी से किये जा रहे काम की स्वयं निगरानी की। घग्गर के साथ लगते प्रभावित इलाकों का जायज़ा लेने के दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जुटे रहने के आदेश देते हुये कहा कि लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरीका, स्पेन जैसे विकसित देशों को भी बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कुदरत ने राज्य में तबाही मचायी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों और पंजाब में लगातार पड़ रही बारिश ने राज्य में यह स्थिति पैदा की है। उन्होंने निचले और बाढ़ की संभावना वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा।

भगवंत मान ने कहा कि वह अपने से पहले मुख्यमंत्रियों की तरह सर्वेक्षण करने के लिए हैलीकॉप्टर पर चक्कर नहीं लगा रहे बल्कि वह ज़मीनी स्तर पर असली स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। स्थिति चिंताजनक है परन्तु फिर भी राज्य सरकार लोगों के नुक्सान को कम करने के लिए हर संभव यत्न कर रही है।

अब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा द्वारा चुपी साध लेना हैरानीजनक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राकृतिक आपदा पर राजनीति खेलने के लिए विरोधी पक्षों पर तीखा निशाना साधते हुये कहा कि इस समय पर वह पंजाबियों को तत्काल राहत पहुँचाने में व्यस्त हैं और उपयुक्त समय आने पर विरोधियों के बयानों का करारा जवाब दिया जायेगा। पटियाला जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग यह डींगे हांक रहे हैं कि केंद्र ने 218 करोड़ रुपए जारी किये हैं, उनको यह याद रखना चाहिए कि यह फंड बीती 10 जुलाई को जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह रकम 72 घंटों में ख़र्च नहीं कर सकती क्योंकि कम से कम नुकसान के लिए सरकार ने पहले ही ज़रुरी प्रयास किये थे। भगवंत मान ने कहा कि घग्गर की सफ़ाई भी राज्य के बाकी सेम- नालों की तरह अच्छी तरह की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की भीख नहीं मंगेगा परन्तु बाढ़ों से हुए नुकसान के अनुमान की रिपोर्ट ज़रूर भेजेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य हमेशा ही पंजाब से पानी और सैस की माँग करते हैं जबकि अब वह अधिक पानी अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य अपना अतिरिक्त पानी राज्य की तरफ बहाव रहे हैं, जिससे पंजाब का बड़ा नुकसान हो रहा है। भगवंत मान ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि अब यह राज्य पंजाब से अपने हिस्से के पानियों पर पूरी तरह चुप हैं और राज्य को बर्बाद करने के लिए फ़ाल्तू पानी हमारी तरफ भेज रहे हैं।

अब 1 लाख रुपए तक के बिलों की कार्यबाद मंजूरी व तस्दीक के अधिकार सिविल सर्जन के पास होंगे

फ़ैसले से पंजाब सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत, मैडीकल बिलों के निपटारे में आएगी तेज़ी

जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ कहा कि वित्त विभाग ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के मैडीकल बिलों के जल्दी निपटारे को यकीनी बनाने के लिए सिविल सर्जन के द्वारा मैडीकल बिलों की कार्यबाद मंजूरी और तस्दीक हद को दोगुना करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पंजाब और चंडीगढ़ के निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए पंजाब सरकार के मुलाजिमों की तरफ से उठाए गए 1 लाख रुपए तक के मैडीकल बिलों की तस्दीक करने और कार्यबाद स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मैडीकल बिलों के निपटारे में आ रही दिक्कतों को मुख्य रखते हुए वित्त विभाग ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई विभाग की तरफ से भेजे गये प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मैडीकल बिलों के निपटारे सम्बन्धित प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण को और मज़बूत करने के लिए लए गए इस फ़ैसले से मैडीकल दावों, बिलों की प्रति-पूर्ति और निपटारे में तेज़ी आएगी।

हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि साल 2010 में वित्त विभाग की तरफ से निजी अस्पतालों के 25000 हज़ार रुपए तक के मैडीकल बिलों के अधिकार सिविल सर्जन को दिए जाने को मंज़ूरी दी गई थी परन्तु इसके बाद इलाज की कीमतों में हुए वृद्धि को देखते किसी ने भी मुलाजिमों के हित में इस हद को बढ़ाने सम्बन्धी कोई फ़ैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के उपरांत 12 साल बाद मई 2022 में ही इस सीमा को दोगुना करते हुए निजी अस्पतालों के इलाज के 50,000 रुपए तक के मैडीकल बिलों के अधिकार सिविल सर्जनों को दिए गए और इससे अधिक के मैडीकल बिलों की कार्यबाद मंजूरी डायरैक्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की तरफ से करने की व्यवस्था की गई है।

पंजाब में 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने लिया फैसला

चंडीगढ़. भारी बारिश के बाद बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई हुई है। पंजाब के कई जिलों में लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ऐसे में पंजाब शिक्षा विभाग के राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। पंजाब के स्कूलों को 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में छुट्टियां 16 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी हैं। 17 जुलाई सोमवार से स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे।

केंद्र ने पंजाब को जारी किया 218.40 करोड़ रुपये का राहत फंड, जाखड़ ने किया धन्यवाद

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

बाढ़ प्रभावित पंजाब में राज्य आपदा से निपटने के लिए तत्काल धनराशि जारी करने और मौजूदा दिशानिर्देशों में ढील देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए भाजपा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य सरकार से अपील की कि वह संकटग्रस्त लोगों तक पहुंचने में और अधिक समय बर्बाद न करे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में फसल क्षति पर किसानों को अविलंब 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।

जाखड़ ने कहा कि भगवंत मान बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केंद्र द्वारा दी गई धनराशि तुरंत वितरित करें और ऐसे समय में गिरदावरी का इंतजार ना करें। उन्होंने कहा कि सभी को तत्काल ठोस राहत देना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज देश के 22 राज्यों को भारी बारिश और संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर मौजूदा दिशानिर्देशों में ढील देते हुए तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को फंड जारी किया है, जिसमें पंजाब को इस उद्देश्य के लिए 218.40 करोड़ रुपये मिले हैं।

फ्रांस गणराज्य के पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 जुलाई 2023 की दोपहर को पेरिस पहुंचे। एक विशेष भावाभिव्यक्ति के रूप में, फ्रांस की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री एलिजाबेथ बोर्न ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमेनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बास्टील-डे परेड में भाग लेंगे। यह यात्रा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उत्सव का भी प्रतीक है।

बाजवा ने हरियाणा को 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की कड़ी निंदा की

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए हरियाणा को 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को कहा कि पंजाब कांग्रेस राजधानी में पंजाब के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि केवल भाजपा नीत केंद्र सरकार ही पंजाब की राजधानी और नदी जल पर उसके दावों को ध्वस्त करने पर आमादा नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ और उसके नदी जल पर पंजाब के दावे को कमजोर करने की भी कोशिश की है। उन्होंने कहा, 'यह चंडीगढ़ प्रशासन का एक गैरकानूनी फैसला है जिसे पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाजवा ने आगे कहा कि हमेशा की तरह, पंजाब कांग्रेस अपनी राजधानी पर पंजाब के दावे की रक्षा के लिए कानून के दायरे में सब कुछ करेगी।

विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है और किसी भी अन्य राज्य या सरकार को राजधानी पर पंजाब के एकमात्र दावों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, 'पिछले साल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट में अलग विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में केंद्र सरकार से जमीन के एक टुकड़े की मांग की थी, जबकि तथ्य यह है कि राजधानी केवल पंजाब की है।

अमित शाह ने जी20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को हरियाणा के गुरूग्राम में एनएफटीज़, एआई और मैटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा, केन्द्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दो दिवसीय सम्मेलन में जी20 देशों, 9 विशेष आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी लोगों, भारत और दुनियाभर के डोमेन विशेषज्ञों सहित 900 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। संबोधन की शुरूआत में केन्द्रीय गृह मंत्री ने तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेज़िलिएन्स स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत का जी20 अध्यक्षता का विषय - 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात 'वन अर्थ - वन फैमिली - वन फ्यूचर' है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह वाक्य शायद आज की 'डिजिटल दुनिया' के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी आज सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और आर्थिक सीमाओं के पार पहुँच चुकी है और आज हम एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हालाँकि, टेक्नोलॉजी मानव, कम्युनिटी और देशों को और करीब लाने वाला एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी हैं, जो नागरिकों और सरकारों को, आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लेह-लद्दाख की तीन दिवसीय यात्रा पर अनुराग ठाकुर, कहा-

भारत-चीन सीमा से सटे गांवों तक जल्द पहुंचेगी फ्री-डिश

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लेह-लद्दाख की तीन दिवसीय यात्रा पर अनुराग ठाकुर

• **जालंधर ब्रीज.** लेह

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत तीन दिवसीय लेह- लद्दाख यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेह से 211 किलोमीटर दूर, भारत- चीन सीमा से लगे गांव 'करजोक' में रात बिताई। इसके अतिरिक्त युवा एवं खेल मामलों के मंत्री ने 14000 फीट की ऊंचाई पर पुगा आवासीय विद्यालय के अपने दौरे के दौरान युवाओं संग वॉलीबॉल भी खेला और युवाओं के आमंत्रण रात्रि में मोबाइल फ़ोन की रौशनी में टेबल टेनिस में भी हाथ आजमाया। ठाकुर ने कहा कि लेह लद्दाख के युवा प्रतिभा से भरे हैं। 2014 से पहले इनकी प्रतिभा को देखने वाला कोई नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में इनकी प्रतिभा को तराशा जा रहा है।" ठाकुर ने कारजोक व पुगा में खेल उपकरण भी वितरित किये. भारत चीन सीमा से सटे गावों के विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भारत-चीन सीमा पर स्थित इलाकों में प्रसारण तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी बढाने के लिये कृत संकल्पित हो कर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम जल्द भारत-चीन सीमा पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को दूरदर्शन फ्री डिश का कनेक्शन उपलब्ध कराएँगे। इसके अलावा बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु भी तेज़ी से कार्य किये जा रहे हैं।" उल्लेखनीय है कि डीडी "फ्री-डिश" प्लेटफार्म के जरिए सीमावर्ती और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिये सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के गांवों में 1.5 लाख मुफ्त "फ्री-डिश" वितरित करने का प्रस्ताव किया था।

ठाकुर ने आगे कहा, 'हम लेह लद्दाख को विकास के मामले में बाकी भारत के समकक्ष लाने हेतु लगातार काम कर रहे हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे सड़क, पुल, टनल इत्यादि के साथ साथ हम यहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित कर रहे हैं. पर्यटन हो या खेल, मोदी सरकार लेह लद्दाख की सभी बुनियादी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करेगी।'

पहलगाम की खूबसूरत वादियों के आप भी हो जाएंगे दीवाने

YATRA

सफेद बर्फ से ढके पहाड़, नीली झील के सुंदर नजारों को देखना चाहते हैं तो पहलगाम जा सकते हैं। यहां घूमने के लिए काफी सारी जगह हैं ऐसे में यहां जानिए पहलगाम में घूमने की जगह।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

पहलगाम भारत के जम्मू-कश्मीर की फेमस डेस्टिनेशन में से एक है। यहां पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस जगह खूबसूरत वादियां और सुंदर नजारों को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ और नीले पानी की झील को देखने के अलावा आप यहां आसपास की जगहों को भी घूम सकते हैं।

चंदनवाड़ी

चंदनवाड़ी जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के बाहरी इलाके में स्थित एक खूबसूरत घाटी है। यह पहलगाम से लगभग 16 किमी दूर है। इस जगह को धार्मिक महत्व के साथ एक पर्यटन स्थल माना जाता है क्योंकि यह पवित्र अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार है।

बैसारन

पहलगाम से सिर्फ 5 किमी दूर बैसरन घाटी कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बैसारन एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित घास का मैदान है, जो घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है।

बेताब घाटी

बेताब घाटी ऊंचे देवदार के पेड़ों और देवदार के जंगलों से घिरी खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसका नाम यहां फिल्माई गई सनी देओल और अमृता सिंह अभिनीत बॉलीवुड फिल्म बेताब से मिला।

पहलगाम बाजार

पहलगाम में ऊनी कपड़े, कालीन, काफ्तान, गलीचे, कश्मीरी हस्तशिल्प और चाय की मिठाइयां जरूर खरीदें। यहां से आप कुछ सुंदर कश्मीरी कढ़ाई वाले शानदार शॉल और ड्रेस मटेरियल खरीद सकते हैं।

शेषनाग झील

शेषनाग झील पहलगाम के सबसे खूबसूरत आकर्षणों में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी और ऊंचे अल्पाइन घास के मैदानों से घिरी यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।

FASHION+

करीना ने इटली वेकेशन के लिए पहनी सस्ती ड्रेस

करीना कपूर इटली में वेकेशन एंज्वॉय कर रही हैं। जहां उनकी स्टाइलिश ड्रेस पर लड़कियों की निगाह लगी है। लेटेस्ट फोटोज में वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की काफी स्टाइलिश ड्रेस पहने हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

करीना कपूर अपने फैशन सेंस से हर किसी को इंप्रेस कर लेती है। कैजुअल आउटिंग के लिए उनका स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक किसी भी लेडी के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। इन दिनों इटली में फैमिली वेकेशन मना रहीं करीना का स्टाइलिश लुक परफेक्ट है। जिसे कोई भी आसानी से वियर कर सकता है। वहीं करीना कपूर ने ऐसी ड्रेस पहन ली जो किसी भी स्टाइलिश लड़की के बजट में आसानी से फिट बैठ जाए।

करीना ने शेयर की तस्वीर

करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पति सैफ अली खान के साथ फोटो शेयर की है। जिसमे वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राईप जर्सी ड्रेस को पहने दिख रही हैं। इस ड्रेस को करीना ने बिल्कुल वाइब्रेंट यलो शूज के साथ पेयर किया है। वहीं बालों को स्लीक बन में बांधा है। हाफ स्लीव और शार्ट राउंड नेक जिस पर व्हाइट कलर की डिटेलिंग है। ड्रेस को काफी स्टाइलिश बना रही है। वहीं ये ड्रेस करीना के स्लिम फिगर को भी परफेक्टली फ्लांट कर रही है।

वहीं पति सैफ ने लाल रंग की हाफ शर्ट और टैन ब्राउन हाफ पैंट के साथ व्हाइट शूज कैरी किए हैं। जिसमे ये कपल बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है।

फिट हो जाएगी बजट में

करीना कपूर का ये लुक कंफर्टेबल और स्टाइलिश है। जिसे लड़कियां बड़े ही आसानी से कैरी कर सकती हैं। मूवी डेट से लेकर शॉपिंग के लिए ड्रेस परफेक्ट है। वहीं इस ड्रेस की कीमत भी कुछ ऐसी है कि सुनकर हैरानी हो सकती है। दरअसल, करीना कपूर ने एचएंडएम फैशन लेबल से इस ड्रेस को पिक किया है। जिसकी कीमत बेहद कम है। एचएंडएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस ड्रेस की कीमत मात्र 1,499 रुपये है। जिसे सुन कोई भी हैरान हो सकता है।

बारिश में चटपटा खाने का करे मन तो बनाएं पोहा टिक्की, चटनी के साथ करें सर्व

बारिश के मौसम में अक्सर चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में आप घर पर ही टेस्टी पोहा टिक्की बना सकते हैं। इन टिक्की को चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

बारिश के सुहावने मौसम में घूमने का मन तो खूब करता है साथ ही कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग होती है। ऐसे में आप टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की बना सकते हैं। वैसे तो लोग आलू की टिक्की खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहां हम बता रहे हैं पोहा से बनने वाली टेस्टी टिक्की की रेसिपी। इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और हरा धनिया की चटनी के साथ सर्व करें।

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए...

- उबले आलू
- पोहा
- बारीक कटी शिमला मिर्च
- बारीक कटी प्याज

- बारीक कटी हरी मिर्च
- लाल मिर्च पाउडर
- काली मिर्च पाउडर
- नमक
- काला नमक
- अदरक-लहसुन पेस्ट
- जीरा पाउडर
- अमचूर पाउडर
- धनिया पाउडर
- हरा धनिया
- कॉर्न फ्लोर

कैसे बनाएं

पोहा से बनी टिक्की बनाने के लिए उबले आलू को अच्छे से मैश करें। फिर पोहा को पानी में भिगोकर छान लें। जब पोहा से सारा पानी निकल जाए तो इसे आलू के साथ मिक्स करें। अब आलू में प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और चावल का आटा डालें। इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और हरा धनिया डालें। अब कॉर्न फ्लोर की स्लरी बनाएं और नमक-काली मिर्च मिलाएं। अब आलू के मसाले से छोटी-छोटी टिक्की बनाएं और फिर इन्हें स्लरी में डिप करें। इसके बाद इसके ऊपर सूखा पोहा लगाएं। गर्म तेल में इन टिक्की को सेक लें और फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें।

बच्चों की परवरिश में माता-पिता को अक्सर झेलनी पड़ जाती हैं ये परेशानियां

PARENTING

बच्चों की परवरिश में पैरेंट्स को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिसके बारे में बात नहीं करते लेकिन केवल फाइनेंशियली ही नहीं इमोशनली भी चैलेंज होते है

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नही है। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसा ढाला जाए वो वैसा ही ढल जाते हैं। ऐसे में पैरेंट्स को उनकी परवरिश के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार वो केवल फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि मेंटली और फिजिकली भी कठिनाईयां झेलते हैं। बहुत सारे पैरेंट्स बच्चों की परवरिश में आने वाले इन चैलेंज पर बात नहीं करते लेकिन लगभग हर बच्चे के माता-पिता को इन चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है।

पैरेंट्स के मन में अपराध बोध होता है- भागदौड़ भरी लाइफ, वर्क लाइफ और एकल परिवार में होने की वजह से मां और पिता दोनों ही बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। ऐसे में बहुत सारी मांओं को इस बात का गिल्ट मन ही मन रहता है कि वो अपने बच्चे के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में वो मेंटली काफी परेशान रहती हैं और बच्चे के प्रति उनके मन में अपराधबोध भरा रहता है।

मांओं को छोड़नी पड़ती हैं इच्छाएं- हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन, बच्चों के आ जाने से इतना काम बढ़ जाता है कि उन्हें अपने शौक और इच्छाओं के लिए समय ही नहीं मिलता। नतीजा वो अपनी पहचान और शौक खोने लगती है। यहां तक कि वो अपने अलग पहचान ही खो देती हैं और केवल किसी बच्चे की मां बनकर ही रह जाती है। बच्चों के बड़े होने के बाद एक समय ये बात मन को काफी ठेस पहुंचाती है।

कपल से ज्यादा पैरेंट्स रह जाते हैं- आजकल हर किसी के पास अपने गोल और काम है। जिसकी वजह से उनके पास समय की कमी होती है। यहां तक कि बच्चे भी जब स्टडी करने लगते हैं तो अपने गोल्स और स्टडी को पूरा करने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में बातचीत, कंवर्शेसन और कम्यूनिकेशन की कमी हो जाती है। जिसकी वजह से कई बार कपल में आपस में बहस होती है। जिसका निगेटिव असर बच्चे पर देखने को मिलता है।

समाज बढ़ा देता है प्रेशर- बच्चों की परवरिश पर सबसे ज्यादा असर सोशल एक्सेपटेंसी का पड़ता है। घर,परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार अक्सर बच्चों की परवरिश में कमी निकालते हैं। फिर वो चाहे उनका बिहेवियर हो या फिर खाने की आदत। जिसका सीधा असर पैरेंट्स पर पड़ता है और वो काफी ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। कि कैसे बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाए।

हार्मोंस इंबैलेंस के लिए इस न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है जिम्मेदार

HEALTH CARE

महिलाओं को अधिकतर हार्मोंस के इंबैलेंस की समस्या से जूझना पड़ता है। जिसके लिए गलत लाइफस्टाइल के साथ ही बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिडी की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है।

• **जलंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

हेल्दी लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि पोषण से भरपूर डाइट को लिया जाए। जिसमे सारे जरूरी मिनरल्स और विटामिन शामिल हो। साथ ही ओमेगा 3 भी जरूर हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड को हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। और, अधिकतर एक्सपर्ट ओमेगा 3 को बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी मानते हैं। लेकिन केवल हार्ट हेल्थ ही नहीं एक्सपर्ट न्यूट्रिशिनिस्ट का मानना है कि ओमेगा 3 हार्मोंस को भी बैलेंस करने का काम करता है। हार्मोंस को बैलेंस करना है तो जरूरी है कि नेचुरल फूड्स खाएं जो ओमेगा 3 से भरपूर हों।

क्यों जरूरी है शरीर के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड

ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के लिए जरूरी फैट है जो बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन ये फैटी एसिड शरीर के कई सारे फंक्शन के लिए जरूरी होता है। जिसमे हार्ट हेल्थ के साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यून फंक्शन शामिल है।

हार्मोंस बैलेंस करने में करता है मदद

ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने, स्ट्रोक का खतरा कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्मोंस को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है।

वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 के रिच सोर्स हैं ये फूड्स

ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट बेस्ड फूड्स के साथ ही सीफूड में खूब मिलते हैं। वेजिटेरियन लोग इन फूड्स से पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 पा सकते हैं।

- चिया सीड्स
- फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज
- अखरोट
- बादाम
- ऑलिव ऑयल
- एवाकॉडो

नॉन वेजिटेरियन ये फूड्स हैं ओमेगा 3 के रिच सोर्स

ओमेगा 3 फैटी एसिड सीफूड में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जिसमे सालमन फिश, साडिंयन फिश के साथ ही मकरैल फिश शामिल है।

हार्मोंस इंबैलेंस के दुश्मन है ये फूड्स

हार्मोंस इंबैलेंस की शिकायत सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। जिसकी वजह से वो काफी सारी समस्याओं थायरॉइड. पीरियड्स प्रॉब्लम, पीसीओएस से परेशान रहती है। ऐसे में उन्हें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये सारे फैट्स हार्मोंस को तेजी से बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।

नोट : इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अमल करने से पहले डाक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

मोदी सरकार के नौ साल - विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण कायाकल्प

संक्षेप में, *मोदी सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। उत्पादन क्षमता के विस्तार, पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क के प्रसार, बिजली को सुलभ बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और व्यापक सुधारों को लागू करने पर ध्यान देकर भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में और ऊंचे लक्ष्य तथा उत्सर्जन में और अधिक कटौती करने के इरादे के साथ, मोदी सरकार ने भारत के विद्युत क्षेत्र के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना जारी रखा है।*

पिछले नौ वर्षों के दौरान, मोदी सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलावों को संभव बनाया है। निरंतर लोड शेडिंग और बिजली की कमी वाले दिन अब इतिहास हो गए हैं। वर्ष 2014-15 से पहले, बिजली की आपूर्ति में होने वाला घाटा आश्चर्यजनक रूप से 4.5 प्रतिशत था। हालांकि, 2014 में इस सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से बिजली उत्पादन क्षमता में 185 गीगावॉट की प्रभावशाली वृद्धि की गई है। इसके साथ भारत बिजली की कमी वाले देश की जगह अधिशेष बिजली वाला देश बन गया है। आज हमारी कुल स्थापित क्षमता 417 गीगावॉट है, जोकि 222 गीगावॉट की चरम मांग से लगभग दोगुनी है। परिणामस्वरूप, भारत अब पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात कर रहा है।

पारेषण (ट्रांसमिशन) के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2013 के बाद से, लगभग दो लाख सर्किट किलोमीटर तक फैली पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है जो पूरे देश को एक ही आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) पर संचालित होने वाले एक एकीकृत ग्रिड से जोड़ता है। इन पारेषण लाइनों में 800 केवी एचवीडीसी जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है और ये समुद्र तल से 15000/16000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर – लेह लाइन सहित कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण व दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 112 गीगावॉट बिजली स्थानांतरित करने की क्षमता ने भारत को एक एकीकृत बिजली बाजार में बदल दिया है, बिजली स्थानांतरित करने की यह क्षमता 2014 में मात्र 36 गीगावॉट की थी। स्थानांतरण की इस क्षमता की सहायता से वितरण कंपनियों को देश भर में किसी भी उत्पादक कंपनी से प्रतिस्पर्धी दरों पर अधिकतम बिजली खरीदने की सहूलियत मिल गई है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलने लगी है।

सभी लोगों तक बिजली पहुंचाना इस सरकार के प्रयासों का एक प्रमुख फोकस रहा है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले, आज़ादी के 67 साल बाद भी 18,000 से अधिक गांव और कई बस्तियां बिजली से वंचित थीं। अगस्त 2015 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1000 दिनों के भीतर हर गांव को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में लॉजिस्टिक से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सरकार ने निर्धारित समय से 13 दिन पहले, केवल 987 दिनों में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2018 में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण खबर के रूप में मान्यता दी थी।

इस सफलता को आधार बनाकर आगे बढ़ते हुए, सरकार ने हर घर को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा। उल्लेखनीय तरीके से, यह लक्ष्य 18 महीनों के भीतर ही हासिल कर लिया गया और कुल 2.86 करोड़ घरों को बिजली से जोड़ा गया। बिजली पहुंचाने की दिशा में यह तेज प्रसार ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से मान्यता मिली है। मोदी सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि कोई भी पीछे न छूटे।

वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, सरकार ने सभी राज्यों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत लागत से व्यापक योजनाएं लागू कीं। इन योजनाओं में नए सबस्टेशनों का समावेश करना, मौजूदा सबस्टेशनों को उन्नत करना, ट्रांसफार्मर की स्थापना और हजारों किलोमीटर लंबी एलटी व एचटी लाइनों का निर्माण एवं उन्हें बदलना शामिल था। इन प्रयासों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता 2015 में 12 घंटे से बढ़कर आज 22.5 घंटे हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब औसतन 23.5 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। परिणामस्वरूप, डीजी सेट का बाज़ार अब समाप्त हो गया है!

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा पर अपना ध्यान केन्द्रित करके पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की है। वर्ष 2015 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2022 तक 175 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। वर्तमान में, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत अतिरिक्त 84 गीगावॉट के साथ भारत ने 172 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इस विकास ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। अपनी इस ख्याति के कारण भारत ने दुनिया भर के प्रमुख कोषों से निवेश को आकर्षित किया है। इसके अलावा, भारत ने निर्धारित समय से नौ साल पहले ही 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता की अपनी प्रतिबद्धता हासिल कर ली है। वर्तमान में, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 43 प्रतिशत हिस्सा यानी कुल 180 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है।

जालंधर ब्रीज

आर.के. सिंह
(केन्द्रीय विद्युत मंत्री)

सरकार उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में भी सफल रही है। वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन की तीव्रता को 33 प्रतिशत – 35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को हासिल करके, भारत ने खुद को वैश्विक तापमान में 2-डिग्री से कम वृद्धि करने के विचार के अनुरूप चलने वाले एकमात्र जी-20 देश और प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, उजाला (एलईडी वितरण), 'प्रदर्शन करें, उपलब्धि हासिल करें और व्यापार करें' (परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी)), उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न कार्यक्रमों ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 159 मिलियन टन की कमी लाने में योगदान दिया है। व्यावसायिक और आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया बिल्डिंग कोड इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। हमने अब 2005 के स्तर के मुकाबले 2030 तक अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को एक बिलियन टन और हमारी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है। इन लक्ष्यों को भी हम 2030 से पहले हासिल कर लेंगे।

संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू किये गये हैं। वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में दक्षता और वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने हेतु वित्तपोषण को एटीएंडसी संबंधी नुकसान में कमी के साथ जोड़ना, ऊर्जा लेखांकन और ऑडिट को लागू करना तथा राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, डिस्कॉम कंपनियों का एटीएंडसी संबंधी नुकसान वित्तीय वर्ष 2021 में 22 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 16.44 प्रतिशत रह गया है। डिस्कॉम कंपनियों के यहां बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों (जेनकॉस) का विरासती बकाया घटकर लगभग आधा – 1.4 लाख करोड़ रुपये से 80 हजार करोड़ रुपये – हो गया है। डिस्कॉम कंपनियों द्वारा ली जाने वाली बिजली के लिए किया जाने वाला वर्तमान भुगतान अद्यतन है।

सबसे कुशल उत्पादन स्टेशनों को पहले शेड्यूल करने संबंधी लचीलेपन की अनुमति देकर, हमने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम कर दी है। 'रीयल-टाइम मार्केट' की शुरूआत के जरिए और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग-अलग 'टर्म अहेड' और 'डे-अहेड मार्केट' स्थापित करके बिजली के बाजार का विस्तार भी किया गया है।

ऊर्जा रूपांतरण की दिशा में प्रयास के तहत, हमने ताप विद्युत संयंत्रों में तापीय ऊर्जा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की बंडलिंग और बायो-मास को-फायरिंग की अनुमति दी है। 100 किलोवाट या इससे अधिक जुड़े भार वाला कोई भी उपभोक्ता अब ऐसे उत्पादन संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। सरकार पीएलआई के जरिए सौर पीवी सेल के उत्पादन और व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को समर्थन प्रदान कर रही है।

जलविद्युत क्षेत्र, जो मंद पड़ा था, को लगभग 15 गीगावॉट की निर्माणाधीन परियोजना के साथ फिर से सक्रिय किया गया है। विद्युत चालित वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग संबंधी अवसंरचना स्थापित करने के नियमों व दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया है और घरेलू कनेक्शन से चार्जिंग संभव हो गई है। विवाद समाधान तंत्र अब एक महीने के भीतर विवाद का निपटारा करता है।

पश्चिमी कमान के सैनिकों द्वारा बाढ़ बचाव एवं राहत अभियान

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब और हरियाणा के नागरिक प्रशासन से प्राप्त मांग के आधार पर, पश्चिमी कमान के बाढ़ राहत दलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और निकासी प्रयासों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए तैनात किया गया।

बचाव और राहत उपायों के प्रावधान के लिए मांग प्राप्त होने पर तुरंत, बाढ़ राहत पूर्व परीक्षण दल को रूपनगर, मोहाली और पंचकुला के प्रभावित क्षेत्रों में भेज गया। जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के बाद, बचाव और राहत दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। सेना की इंजीनियर टुकड़ियों के साथ बचाव दल ने फंसे हुए लोगों को निकालने

के लिए रात भर काम किया और बाढ़ के पानी से नहरों को टूटने से बचाने में मदद की। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 50 नागरिकों और चितकारा विश्वविद्यालय के 910 छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिरोजपुर जिले के अराजी सबरन गांव में, महिलाओं और बच्चों सहित 44 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

एक बड़े प्रयास में, सेना के इंजीनियरों की टुकड़ियों ने तटबंध की मुरम्मत करके सरहिंद नहर के टूटने को रोकने में मदद की, जिससे दोराहा गांव और आसपास के इलाकों में बाढ़ को रोका जा सका।

सेना नागरिक प्रशासन और सभी हितधारकों के समन्वय में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। सेना द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद करने के लिए सभी सहायता प्रदान करना जारी है।

बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा करेंगे अनुराग ठाकुर

हिमाचल. 12 जुलाई , हिमाचल प्रदेश : केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आगामी 14, 15, 16 जुलाई को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होंगे। अनुराग ठाकुर बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा कर भारी बारिश से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा " देवभूमि हिमाचल इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई जगहों पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है व जान-माल का नुक़सान देखने को मिल रहा है। विपदा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं देवभूमि के मेरे भाइयों बहनों के साथ हैं। आगामी 14, 15, 16 जुलाई को अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बाढ़ प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण कर बारिश से प्रभावित लोगों से मिलूँगा उनका दर्द साझा करूँगा व सरकार की ओर से हो सकने वाली हर संभव मदद दिलवाने का प्रयास करूँगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल के हालातों पर पूरी तरह नज़र बनाए रखी है।एनडीआरडीए की 12 टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ रात-दिन राहत व बचाव कार्यों में लगी है" आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा "भारी बारिश के चलते हो रहे जान-माल के नुक़सान की घटनाएँ दुःखद हैं। मैं निरन्तर ज़िला प्रशासन व अधिकारियों के संपर्क में हूँ।

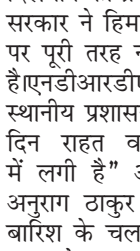

पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे देखेंगे चंद्रयान-3 की सफलता का नजारा, श्रीहरिकोटा के लिए भर चुके हैं उड़ान

श्रीहरिकोटा से होने वाले प्रक्षेपण के लिए इसरो जोर-शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस पल के साक्षी बनने के लिए पंजाब के सरकारी स्कूलों के 40 बच्चे भी श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 4 साल बाद एक बार फिर चांद पर चंद्रयान पहुंचाने की तैयारी में है। आज इसरो पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चांद पर अपना तीसरा चंद्रयान पहुंचाने वाला है। चांद की सतह पर अगर चंद्रयान की 'सॉफ्ट लैंडिंग' हो जाती है तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जो ऐसा करने में सफल हुए है। पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण होने वाले चन्द्रयान 3 के साक्षी बनने के लिए तैयार है।

स्कूल ऑफ एमिनेंस के 40 स्टूडेंट्स को चन्द्रयान 3 का साक्षी बनने के लिए श्रीहरिकोटा भेजा गया है। मोहाली के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज इन 40 स्टूडेंट्स ने श्रीहरिकोटा पहंचे।

23 जिलों के 40 बच्चे बनेंगे चन्द्रयान 3 के साक्षी : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा मुख्यमंत्री भगवंत मान की परिकल्पना स्कूल ऑफ एमिनेंस (एसओई) के छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। पंजाब के विभिन्न जिलों से एसओई के 40 छात्र चन्द्रयान 3 के प्रक्षेपण को देखने के लिए श्रीहरिकोटा के लिए उड़ान भर रहे हैं। इस 3 दिवसीय यात्रा पर, वे श्रीहरिकोटा की पूरी सुविधा भी देखेंगे और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति के बारे में जानेंगे। छात्रों के लिए भी यह एक नया अनुभव होगा। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है।

2019 में चांद की सतह पर उतरने में विफल रहा था चंद्रयान-2 : आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में चांद की सतह पर चंद्रयान-2 की लैंडिंग नहीं हो पाई थी। जिसकी वजह से इसरो की टीम निराश हो गई थी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भावुक हुए तत्कालीन इसरो प्रमुख के। सिवान को गले लगाकर ढांढस बंधाया था। वो तस्वीर आज भी लोगों को याद है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता की ओर आगे बढ़ना

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज में हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदायों, जैसे एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक, सफाई कर्मचारी आदि के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले नौ वर्षों में इन समुदायों के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। पिछले नौ वर्षों में, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की गयीं हैं।

"भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति" का उद्देश्य सबसे गरीब घरों के अनुसूचित जाति के छात्रों के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। 2019-20 के दौरान 11-12वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 52.9% था, जो 2020-21 के दौरान बढ़कर 56.1% और 2021-22 के दौरान 61.5% हो गया। 2014-15 से अनुसूचित जाति के 4.87 करोड़ से अधिक छात्रों को लगभग 29828.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। "अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना", अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। 2019-20 के दौरान 9-10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 83% था, जो 2020-21 के दौरान बढ़कर 84.8% और 2021-22 के दौरान 84.9% हो गया। 2014-15 से अनुसूचित जाति के 2.31 करोड़ से अधिक छात्रों को 3528.17 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। "उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस) तथा निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस)" के तहत एससी और ओबीसी के 19995 से अधिक छात्रों को 2014-15 से केंद्रीय सहायता के रूप में 109.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। "एससी के लिए शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति योजना (टीसीएस)" के तहत 2014-15 से 21988 से अधिक एससी छात्रों को केंद्रीय सहायता राशि के रूप में 399.15 करोड़ रुपये जारी किए गए। "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना (एनओएस)" के तहत अनुसूचित जाति, गैर- अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों के 950 से अधिक चयनित छात्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में 2014-15 से 222.24 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी। "एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)" के तहत 2014-15 से 21066 से अधिक छात्रों को केंद्रीय सहायता राशि के रूप में 1628.89 करोड़ रुपये जारी किए गए। "लक्षित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)" के तहत 2014-15 से 3.18 लाख से अधिक छात्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में 457.22 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) का लक्ष्य कौशल विकास, आय-सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा सृजन करना है। पीएम-एजेएवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 03 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं -

जालंधर ब्रीज

डॉ वीरेंद्र कुमार
(लेखक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं।)

(i) पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का आदर्श ग्राम घटक; 2022-23 में 11500 अन्य गांवों को भी शामिल किया गया है; 4351 गांवों को पहले ही आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है (ii) अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीए से एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता; वित्तीय सहायता 50,000 रुपये या परियोजना लागत का 50%, जो भी कम हो, प्रति लाभार्थी या परिवार है (iii) छात्रावास घटक {पूर्ववर्ती बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)}। पीएम-एजेएवाई योजना के तहत 2023-24 के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 2050.00 करोड़ रुपये है।

"राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्रवाई (नमस्ते)" का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की मौत को रोकने और स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सफाई कार्यों के मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। "हाथों से मैला सफाई करने वाले सफाईकर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना (एसआरएमएस)" के एक भाग के रूप में, 2014-15 से ऐसे 22,294 सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया गया है। 508 जिलों ने कर्मियों द्वारा मैला सफाई की प्रथा से स्वयं को मुक्त घोषित कर दिया है।

"अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)" वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय, वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय संपर्क या गरिमापूर्ण जीवन की सुविधा देती है। 2014-15 से 6,67,330 लाभार्थियों को 511.81 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। 2019-20 से 2022-23 तक "वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्ययोजना (एसएपीएसआरसी)" योजना के तहत 43.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2017-18 से, आरवीवाई के तहत आयोजित 265 शिविरों में 2,99,942 लाभार्थियों को 24,649.98 लाख रुपये की कीमत के कुल 12,24,645 उपकरण वितरित किए गए हैं।

"नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)" 15 अगस्त 2020 को 32 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के 272 जिलों के लिए तैयार और लॉन्च किया गया था। अभियान की गतिविधियों में लगभग 3.08 करोड़ से अधिक युवाओं, 4,000 से अधिक युवा मंडलों, एनवाईकेएस और एनएसएस के स्वयंसेवकों और युवा क्लबों ने भाग लिया है। देश भर के 6000 से अधिक स्कूलों के 13 लाख से अधिक छात्रों के साथ संपर्क स्थापित किया गया है।

"प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष)" का उद्देश्य नौकरी खोजने या स्व-रोज़गार उद्यम शुरू करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2020-21 में लाभार्थियों की संख्या लगभग 32097 और 2022-23 में लभग 35484 थी।

हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पिछले 9 वर्षों से समाज के वंचित वर्ग के सम्मान, प्रगति और सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहा है और मंत्रालय ने प्रतिष्ठित उपलब्धियाँ भी हासिल कीं हैं।

हाईवे के रख-रखाव के कामों में हो रही करोड़ों की धांधली

• **जालंधर ब्रीज.** विशेष रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनावी मोड में आ चुके हैं और अपने सांसदों और मंत्रियों को दो टूक कह चुके हैं कि सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों के बीच जाकर जमीनी स्तर पर बताएं कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर हर चुनौती को कैसे संभाला और देश 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा पिछड़ों से लेकर गरीब, दलित की जीवनशैली को सुधारने के लिए बहुत काम किया।

वहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी क्रांति लाने का काम किया। इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ने अपने फायर ब्रांड मंत्री नितिन गडकरी को नेशनल हाइवे विभाग सौंपकर किया।

उनके 9 साल के कार्यकाल में हासिल की गई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट में जो उपलब्धियां हासिल की है इसके प्रचार के लिए भी नितिन गडकरी को लगाया और हर अपने भाषण में क्या वो कर रहे है और क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार करते अक्सर देखे जाते हैं। लोग उनके किए हुए कामों को सराहना भी करते हैं परंतु वो अकसर कई बार एक्सीडेंट की रोकथाम में फेल होने को लेकर भी खुले मन से स्वीकार करते हैं। इसके लिए किसी विभाग के मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना सही नहीं हैं।

जो भ्रष्ट हाईवे अधिकारी रख-रखाव के काम में कोताही बरत रहे हैं उन पर कार्यवाही न करना उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इसके उदाहरण तो अनेक हैं परंतु अमृतसर-पानीपत हाईवे पर रख-रखाव के नाम पर हो रही करोड़ों की धांधली करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए सीबीआई को अभी तक क्यों नहीं लिखा गया ? अगर लिखा भी गया तो इस पर जमीनी स्तर पर असर क्यों नहीं दिखा ?

आज भी लोग करोड़ों रुपया टोल टैक्स के रूप में अदा करने के बावजूद हाईवे पर टूटी सड़कों से गुजरने के लिए मजबूर हैं।

हाईवे पर थोड़ी-सी बारिश पड़ने के बाद समुद्र जैसे हालात बन जाते हैं जो एक्सीडेंट का मुख्य कारण बनते हैं परंतु पेट्रोलिंग अधिकारियों को तो ठेकेदार से कमीशन लेने और दफ्तर में बैठे अधिकारियों को बिल पास करने से मतलब होता है। चाहे वो टूटी सड़क का हो या सही सड़क का, क्योंकि रख-रखाव तो बिलों में हो रहा है जमीनी स्तर पर तो हादसे ही हो रहे है।

लोगों की सुरक्षा पंजाब सरकार की प्राथमिकता : बलकार सिंह

स्थानीय निकाय मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा

• **जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़**

स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने वीरवार को लोहियां से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और यहां लोगों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस बीच उन्होंने यहां सेहत विभाग की तरफ से लगाए गए मेडीकल कैंपों का निरीक्षण किया और वहां लोगों को मिल रही सेहत सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। निकाय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार लोगों के साथ संकट की इस घड़ी में पूरी तरह से खड़ी है और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है।

उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमों को तैनात किया गया है, जोकि दिन-रात लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने का काम कर रही हैं। इसी तरह राहत कार्यों के तहत लोगों तक खाना, रसद और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए अलग से टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने राज्यसभा मेंबर व पर्यावरणविद संत बलवीर सिंह सींचेवाल का आभार व्यक्त किया, जो दिन-रात इस इलाके में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत सींचेवाल की तरफ से इलाके में लोगों की मदद के लिए वालंयिटर्स की नियक्ति की गई हैं और दिनरात लोगों तक जरूरत का हर सामान पहुंचा रहे हैं। मंत्री बलकार सिंह ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए सभी जिलों को फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं ताकि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए फंड्स और संसाधनों की कोई कमी नहीं है और जल्द ही हम सब मिलकर इस चुनौती से पार पा लेंगे। उन्होंने दोहराया कि लोगों की जानमाल की रक्षा करना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुश्किल घड़ी में अफ़वाहों से दूर रहें और यदि कोई शरारती तत्व झूठी अफ़वाहें फैला कर माहौल ख़राब करता है तो उस सम्बन्धी जानकारी तुरंत ज़िला प्रशासन को मुहैया करवाई जाये।

मान ने पंजाब को 'धरना मुक्त' नहीं 'धरना युक्त' बनाया : जयवीर शेरगिल

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने चुनाव से पहले किए वादों को पूरा नहीं करने और समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर तीखा हमला बोला है। यहां कड़े शब्दों में जारी एक बयान में शेरगिल ने कहा कि जब से आप ने पंजाब की सत्ता संभाली है, तब से राज्य में लगातार धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अलावा, किसान, शिक्षक, बेरोजगार युवा, ग्रामीण, डॉक्टर और उद्योगपति उनकी उचित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने के चलते ऐशो आराम पार्टी के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, मान ने स्पष्ट रूप से पंजाब को 'धरना मुक्त' बनाने का वादा किया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि धोखे और कुशासन की इनकी नीतियों के कारण, आप सरकार ने पंजाब को एक 'धरना युक्त" राज्य बना दिया है।

सांसद व डीसी ने लिया बांध में आई दरार को भरने के कार्य का जायजा

कहा- पंजाब सरकार आम लोगों की बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

सांसद सुशील कुमार रिंकू और डीसी विशेष सारंगल ने वीरवार को गट्टा मुंडी कासू में सतलुज किनारे बांध में आई दरार को भरने के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांध में आई दरारों की मरम्मत का काम भी तेज किया जा रहा है। सांसद व डीसी ने गांव में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया और इस कहा कि प्रशासन की तरफ से पानी को गांव में जाने से रोकने के लिए दरारों को भरवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है या फिर बांध कमजोर है, वहीं पर हजारों की तादाद में रेत व मिट्टी से भरी बोरियां डलवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों की सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकता पर रखा गया है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों तक जरूरत का सारा सामान पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से रिलीफ फंड भी जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से पहले दिन से ही लोगों तक खाना व अन्य सामग्री इत्यादि पहुंचाई जा रही है।

एडीसीपी ट्रैफ़िक जालंधर कंवलप्रीत सिंह चाहल ने आरटीए बलजिंदर सिंह ढिल्लों के साथ मीटिंग की जिसमें फैसला लिया कि भविष्य में अगर कोई ई-रिक्शा बिनां रजिसट्रेशव व ड्राईवर बिनां लाइसैंस के पाया गया तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

11 सरकारी स्कूलों को दिए 11.63 लाख रुपए के चैक

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

चेयरपर्सन जिला योजना कमेटी होशियारपुर कर्मजीत कौर ने आज जिले के 11 सरकारी स्कूलों को पीने वाले पानी के लिए वाटर कूलर व सबमर्सीबल पंप लगवाने के लिए 11.63 लाख रुपए के चैक सौंपे। वीरवार अपने कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी(से) हरभगवंत सिंह व जिला शिक्षा अधिकारी(ए) संजीव गौतम को चैक सौंपते हुए चेयरपर्सन जिला योजना कमेटी ने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल कार्य किए जा रहे हैं। चेयरपर्सन जिला योजना कमेटी ने कहा कि आज सरकारी हाई स्कूल कमालपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनहोता, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल लंगरपुर, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल नंगल खुर्द, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल सींघोवाल, सरकारी हाई स्कूल कोट पटियाल, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल रसूलपुर, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल खिच्चियां, सरकारी प्राइमरी स्कूल शेरगढ़, सरकारी प्राइमरी स्कूल भीखोवाल व सरकारी एलीमेंट्री स्कूल बाडिय़ा कलां में वहां की जरुरत के हिसाब से वाटर कूलर व सबमर्सीबल पंप लगवाने के लिए राशी दी गई है। इस मौके पर उनके साथ आंकड़ा सहायक धरमिंदर सिंह, जूनियर सहायक विजय कुमार भी मौजूद थे।

प्रदूषण निकाय व सिंचाई विभाग की नालायकी के कारण पंजाब में हुए ऐसे हालात

• बाढ़ आने के बावजूद नहीं रुक रही बावा खेल नहर में गंदगी और कब्जे। **(फोटो- जालंधर ब्रीज)**

• **जालंधर ब्रीज.** विशेष रिपोर्ट

पंजाब में ना तो कोई कुदरती स्रोत है जिसका प्रयोग हर वर्ग करके उसको व्यवसाय में तब्दील कर सके। पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किसानी पर निर्भर है। पंजाब के शहरी वर्ग हो या देहाती वर्ग सीधे तौर से किसानों पर निर्भर है। लेकिन पंजाब के किसानी को खत्म करने के लिए कुछ विभाग के अफसरों ने जैसे ठेका ले लिया हुआ है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें पंजाब एक ऐसा सूबा है जो भारत में सबसे प्रमुख फसल चावल को देश और विदेश दोनों की आपूर्ति करता है परंतु इसकी पैदावार कैसी होगी यह मौसम पर निर्भर है। क्योंकि भारत में मौसम बदलता रहता है। यहां कब बारिश होगी कब नहीं, यह पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

मौजूदा समय पंजाब जिस हालात से गुजर रहा है, इसके लिए प्रदूषण निकाय व सिंचाई विभाग के अफसर जिम्मेवार हैं और साथ ही जिले के डिप्टी कमिश्नर भी उतना ही जिम्मेवार हैं। जिन्होंने आने वाले मानसून सीजन के मद्देनजर जिलों में पड़ते नदी, नालों की समय रहते साफ-सफाई नहीं करवाई जिससे ओवरफ्लो से बचा जा सकता था।

जिस पानी को ख़तरे के निशान तक पहुंचने के बाद छोड़ा गया, क्या उसे पहले भी संभाल सकते थे ? जिलों में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति इसलिए नहीं की जाती कि शहर में किसी आपदा से निपटने के लिए क्या-क्या है। इसलिए की जाती कि इससे निपटने के लिए क्या-क्या नहीं है; उसको समय रहते पूरा करवाए।

परंतु डिप्टी कमिश्नर तो राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में लगे रहे और प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी भूल ही गए लेकिन हर मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली फोटो लेना नहीं भूले। जिन अफसरों की नलायकी की वजह से बाढ़ के हालात बने हैं उनको सीधे तौर पर दोषी ठहराना चाहिए।

अगर 21वीं सदी में भी हम यही बयान देंगे कि यह कुदरती आपदा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते... तो फिर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके यह क्यों दिखाना कि प्रशासन ने आपदा में दिन-रात एक कर दिया है।

सोशल मीडिया भी 21वीं सदी की देन है उसको आविष्कार करने वाला यह सोच लेता कि यह भी कुदरती देन है। फोटो फेसबुक पर कुदरत ने लगानी थी आदमी ने खुद नहीं।

सर्वाधिक रनों के मामले में रोहित शर्मा ने केन विलियमसन को छोड़ा पीछे

डोमिनिका. डोमिनिका में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में एक महीने के ब्रेक के बाद टीम इंडिया 12 जुलाई (बुधवार) को मैदान पर उतरी। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टीम के लिए स्टार थे। उन्होंने पहले दिन पांच विकेट लेकर कैरेबियाई टीम को चौंका दिया था। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 150 रन पर सिमट गई। जवाब में, भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने पहले दिन के अंत तक नाबाद 80 रन जोड़े। रोहित शर्मा 30 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि जयसवाल 40 रन बनाकर नाबाद हैं, भारत पहली पारी में केवल 70 रन से पीछे है।

इस बीच रोहित शर्मा ने अपने नाबाद 30 रनों के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में आईसीसी नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया। पारी शुरू करने से पहले वह विलियमसन से 27 रन पीछे थे और अब उनके नाम पर 17145 रन हैं जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान ने अब तक अपने

अंतरराष्ट्रीय करियर में 17142 रन बनाए हैं। इसके अलावा सक्रिय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पांचवें स्थान पर हैं।

इस मामले में विराट कोहली 25385 रनों के साथ टॉप पर हैं जबकि जो रूट 18000 से ज्यादा रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। विलियमसन को पछाड़कर रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर हैं और अगर वॉर्नर को 19 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होने वाले चौथे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया जाता है तो वह इस मामले में वॉर्नर से भी आगे निकल सकते हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.